वित्त मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम):(क) से (ग) इस योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक पूर्ण गोपनीयता है जिसे घोषणाकर्ताओं के संबंध में बनाए रखा जाना है। इस योजना की प्रतिक्रिया काफी हद तक उक्त गोपनीयता में बनाए रखने में विभाग की क्षमता पर भावी घोषणाकर्कताओं के विश्वास पर निर्भर करेगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस योजना में यह व्यवस्था है कि घोषणाएं केवल आयकर आयुक्तों के पास प्रस्तुत की जाएंगी। इस कारण से घोषणाकर्ताओं की संख्या अथवा घोषित की गई धनराशि आदि के बारे में आयुक्तों से केन्द्रीयकृत रूप से ब्यौरे प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के प्रचालन की अवैधि के समाप्त होने पर स्थिति की समीक्षा की जाए।

Prc-Shipmcnt inspection scheme

*88. SHRI NILOPAL BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are discussing the introduction of a Prc-shipmcnt Inspection Scheme to be introduced for evaluating customs duties leviable for imports into India;

(b) if so, whether Government have initiated talks with any foreign company for the purpose; and

(c) if so, the names of the companies and the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Several complaints have been received from time to time about undervaluation and mis-classification of imported goods leading to loss of revenue as also undue delays in cargo clearance at the ports and airports. With a view to overcoming these problems, Government have been considering several measures. Recently, the Directorate of Valuation has been set up to disseminate information on international prices and also monitor valuation practices in the Customs formations. One of the suggestions that came up for consideration in this regard was the use of pre-shipment inspection for ensuring correct classification and valuation of imported goods. It is in this context four pre-shipment companies made presentations on the role of pre-shipment inspection. No decision has been taken in the matter.

Appointment of Judges

*89. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the existing rules dealing with the appointment of Judges of High Courts and the Supreme Court;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether these amendments will not give benefits of favouretism to appointees;

(d) whether removal of these judges will continue to be with the orders of the President of India; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINSITER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) to (c) The Government had decided to make changes in the existing procedure for appointment of Judges of Supreme Court, Chief Justices and Judges of High Courts. Accordingly, the Constitution (Eighty-Second Amendment) Bill, 1997 was forwarded to the Lok Sabha Secretariat on 14th March, 1997.

(d) and (e) Provisions already exist in Articles 124(4) and 217(1) of the Constitution of India in respect of removal of the Judges of the Supreme Court and High Courts on the grounds of misbehaviour or incapacity.

New Civil Aviation Policy

*90. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
DR. MOHAN BABU:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have had under consideration a new Civil Aviation Policy;

(b) if so, the decision taken thereon, indicating details of the policy; and

(c) whether the new policy takes care of the reservation and objections expressed by the Prime Minister during his last visit to Nepal; if so, the steps contemplated thereunder to remove such shortcomings?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI CM. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The policy is awaiting the approval of the Government.

मादक पदार्थों की तस्करी

*91. **प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा**:

श्रीमती मालती शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(c) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(d) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(e) उक्त अवधि के दौरान, वर्षवार कितने मूल्य का मादक पदार्थ पकड़ा गया;

(f) क्या सरकार मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का विचार रखती है; और

(g) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) मादक पदार्थों अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया है अत: यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ रही है अथवा नहीं। तथापि, उपलब्ध सुचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का ब्यौरा इस प्रकार है;

मामलों की संख्या तथा जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा (**किलोग्राम में**)

क्र. सं.	मादक पदार्थ		1995	1996	1997 (अक्तूबर तक)
1.	अफीम	जब्ती मामले	1339 871	2875 977	873 506
2.	मारफीन	जब्ती मामलें	4	4	16
3.	हेराइन	जब्ती मामले	1678 3236	1257 3043	945 2296
4.	गांजा	जब्ती मामले	121873 5737	62992 5833	56978 4749
5.	हशीश	जब्ती मामले	3629 2691	6520 2593	1678 1540
6.	मैथाक्वालॉन	जब्ती मामले	20485 196	2212 405	38 157

मादक पदार्थों का मूल्य निर्धारण, जो प्रात: अनिधारित क्षमता नष्ट किए जाने योग्य होते हैं, संभव नहीं है। स्वर्ग तथा अन्य निषिद्ध माल के विपरीत मादक पदार्थों का कोई वैध बाजार नहीं है। अवैध

बाजार में मूल्य निर्धारण मादक पदार्थों का प्रकार व शुद्धता, विक्रय के स्थान की भौगोलिक स्थिति (अर्थात उदगम के स्नोत से दूरी), वर्ष का समय (अर्थात फसल का मौसम, पर्यटक मौसम), प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी